



हिन्दी दैनिक

पथ प्रवाह

RNI No.: UTTHIN/2011/39282

हर खबर पर पैनी नजर



वर्ष:5 अंक:38 पृष्ठ:08 मूल्य:1 रूपये

pathpravah.com

हरिद्वार, गुरुवार, 12 फरवरी 2026

सूबे के जिलों में 'शी फॉर स्टेम' के तहत पांच छात्राओं को मिलेगी छात्रवृत्ति : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

20 प्रतिभाशाली बेटियों को 50-50 हजार की छात्रवृत्ति वितरित, स्त्रक्षरूस्टार्टअप हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की घोषणा

पथ प्रवाह, देहरादून।

अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस के अवसर पर उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, सुद्धोवाला (प्रेमनगर, देहरादून) में आयोजित 'शी फॉर स्टेम उत्तराखण्ड' विषयक कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग करते हुए महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान 'शी फॉर स्टेम' पहल के अंतर्गत प्रदेश की 20 प्रतिभाशाली छात्राओं को 50-50 हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 'शी फॉर स्टेम' योजना के तहत अब प्रदेश के प्रत्येक जनपद में पांच छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाएगी। साथ ही स्त्रक्षरू (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एवं मैथमेटिक्स) क्षेत्र में स्टार्टअप आरंभ करने की इच्छुक छात्राओं को वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। महिला प्रौद्योगिकी केंद्रों से स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर तकनीकी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पहल प्रदेश की बेटियों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि दूरस्थ एवं सीमांत क्षेत्रों में विज्ञान, नवाचार और आधुनिक तकनीक को पहुंचाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

इतिहास से आधुनिक भारत तक नारीशक्ति का योगदान

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय इतिहास नारीशक्ति के वैज्ञानिक और बौद्धिक योगदान का साक्षी रहा है। वैदिक काल में गर्गी और



मैत्रेयी जैसी विदुषियों ने दार्शनिक विमर्श में अग्रणी भूमिका निभाई, जबकि लीलावती ने गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आयुर्वेद के ग्रंथों के विकास में भी महिलाओं की भागीदारी के प्रमाण मिलते हैं। आधुनिक भारत का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्ना मणि ने देश की पहली महिला मौसम वैज्ञानिक बनकर इतिहास रचा। कमला सोहोनी विज्ञान में पीएचडी प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला बनीं। डॉ. टेसी थॉमस ('मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया') ने अग्नि-4 और अग्नि-5 जैसी परियोजनाओं का नेतृत्व किया, वहीं डॉ. ऋतु करिधल ('रॉकेट वुमन') ने मंगलयान मिशन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उन्होंने कहा कि आज भारत में स्त्रक्षरूक्षेत्रों से स्नातक होने वाले विद्यार्थियों में लगभग 42-43 प्रतिशत छात्राएं हैं, जो कई विकसित देशों की तुलना में अधिक है। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि देश की बेटियां विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नेतृत्व के लिए तैयार

हैं।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विज्ञान एवं तकनीक को नई ऊंचाइयों

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विज्ञान एवं तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। कोरोना वैक्सीन निर्माण, चंद्रयान-3, आदित्य रा और गगनयान मिशन जैसी सफलताओं ने देश को वैश्विक पहचान दिलाई है। डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग को बढ़ावा देकर भारत तकनीकी क्रांति में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की डिजिटल साक्षरता बढ़ाने और स्त्रक्षरूमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र एवं राज्य स्तर पर अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम, प्रगति छात्रवृत्ति योजना, इस्पायर योजना, अटल इनोवेशन मिशन तथा महिला वैज्ञानिक योजना के माध्यम से बालिकाओं और



महिलाओं को शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार से जोड़ा जा रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में भी स्त्रक्षरूमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रावधान किए गए हैं।

उत्तराखण्ड में विज्ञान एवं नवाचार का सुदृढ़ इकोसिस्टम

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड की पहली विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति लागू की है। साइंस एवं इनोवेशन सेंटर, लैब्स ऑन व्हील्स, जीएसआई डैशबोर्ड, डिजिटल लाइब्रेरी, पेटेंट सूचना केंद्र और स्त्रक्षरूलैब्स के माध्यम से विश्वस्तरीय अवसरचर्चा विकसित की जा रही है। एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन, सेमीकंडक्टर तथा प्री-इनक्यूबेशन लैब की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। देहरादून में देश की पांचवीं साइंस सिटी का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जो राज्य को विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में नई पहचान देगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह साइंस सिटी उत्तराखण्ड को वैश्विक विज्ञान

डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

'उत्तराखण्ड का दशक' संकल्प की ओर अग्रसर

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021 में बाबा केदार की भूमि से प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त कथन— '21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखण्ड का दशक होगा'—का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार 'विकल्प रहित संकल्प' के साथ इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यरत है। उन्होंने कहा कि यह संकल्प तभी साकार होगा जब प्रदेश की प्रत्येक बेटि सशक्त, आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सक्षम बनेगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि 'शी फॉर स्टेम' जैसे प्रयास प्रदेश की बेटियों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर करेंगे और वे अपने ज्ञान व कौशल से देश और प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। कार्यक्रम में विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, सचिव रंजीत सिन्हा, महानिदेशक यूकोस्ट प्रो. दुर्गेश पंत सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

जन गण मन से पहले गाया जाएगा वंदे मातरम स्कूलों में राष्ट्रगीत के बाद शुरू होगी पढ़ाई; सिनेमाघरों को छूट

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों या अन्य औपचारिक आयोजनों में 'वंदे मातरम' बजाया जाएगा। इस दौरान हर व्यक्ति का खड़ा होना अनिवार्य होगा। यह आदेश 28 जनवरी को जारी हुआ, लेकिन मीडिया में इसकी जानकारी 11 फरवरी को आई। आदेश में साफ लिखा है कि अगर राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' और राष्ट्रगान 'जन गण मन' साथ में गाए या बजाए जाएं, तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। इस दौरान गाते या सुनने वालों को सावधान मुद्रा में खड़ा रहना होगा।

आदेश के मुताबिक सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत बजाने के बाद ही होगी। नए नियमों के अनुसार, राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे, जिनकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकेंड है। अब तक मूल गीत के पहले दो अंतरे ही गाए जाते थे। हालांकि, आदेश में यह भी कहा गया है कि किन-किन मौकों पर राष्ट्रगीत गाया जा सकता है, इसकी पूरी लिस्ट देना संभव नहीं है। यह पहली बार है जब राष्ट्रगीत के गायन को लेकर डिटेल्ड में प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं। केंद्र इस समय वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम मना रहा है। राष्ट्रपति के आगमन और झंडारोहण जैसे कार्यक्रमों में गाया जाएगा

नई गाइडलाइन के अनुसार, तिरंगा फहराने, किसी कार्यक्रमों में राष्ट्रपति के आगमन, राष्ट्र के नाम उनके भाषणों और संबोधनों से पहले और बाद में, और राज्यपालों के आगमन और भाषणों से पहले और बाद में सहित कई आधिकारिक अवसरों पर वंदे मातरम बजाना अनिवार्य होगा। मंत्रियों या अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मौजूदगी वाले गैर-औपचारिक लेकिन जरूरी कार्यक्रमों में भी राष्ट्रगीत सामूहिक रूप से गाया जा सकता है, बशर्ते इसे पूरा सम्मान और शिष्टाचार के साथ पेश किया जाए। 10 पेजों के आदेश में, सिविलियन पुरस्कार समारोहों, जैसे कि पद्म पुरस्कार समारोह या ऐसे किसी भी कार्यक्रम में जहां राष्ट्रपति उपस्थित हों, वहां भी वन्दे मातरम बजाया जाएगा।

सिनेमा हॉल में लागू नहीं होंगे नए नियम

हालांकि, सिनेमा हॉल को नए नियमों से दूर रखा गया है। यानी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले 'वंदे मातरम' बजाना और खड़ा रहना अनिवार्य नहीं होगा।

वहीं अगर किसी न्यूजरील या डॉक्यूमेंट्री फिल्म के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत बजाया जाता है, तो दर्शकों के लिए खड़ा होना जरूरी नहीं होगा। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी स्थिति में खड़े होने से प्रदर्शन में व्यवधान और अव्यवस्था हो सकती है।

सूबे में शैक्षणिक संवर्ग का बनेगा त्रि-स्तरीय ढांचा: डॉ. धन सिंह रावत

पथ प्रवाह, देहरादून

विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत शैक्षणिक संवर्ग का नया त्रि-स्तरीय ढांचा बनाया जायेगा। जिसका प्रस्ताव शीघ्र ही कैबिनेट में लाया जायेगा। इसके अतिरिक्त डायटों में रिक्त प्रवक्ता संवर्ग के 222 रिक्त पदों को भरने के लिये अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेजा जायेगा ताकि उक्त पदों पर स्थाई नियुक्ति की जा सके। नये शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पूर्व प्रदेशभर के सभी विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा दी जायेगी।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज शासकीय आवास पर शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने केन्द्रीय विद्यालयों की भांति प्रदेश में शिक्षकों के त्रि-स्तरीय ढांचे के गठन में देरी पर विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने अधिकारियों को शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। साथ ही सभी जनपदों के डायटों में लम्बे समय से रिक्त चल रहे प्रवक्ता संवर्ग के 222 पदों को भरने के लिये अध्याचन राज्य लोक सेवा आयोग को भेजने के निर्देश दिये ताकि उक्त पदों के सापेक्ष प्रतिनियुक्ति



पर तैनात प्रवक्ताओं को उनके मूल विभाग में वापस भेजा जा सके।

विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि नये शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले सभी विद्यालयों में सरकार द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जायें। यदि किसी विद्यालय में समय पर पुस्तकें उपलब्ध नहीं होंगी तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने एससीआईआरटी के ढांचे के गठन एवं नियमावली बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। इसके अलावा डॉ. रावत ने चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की नियुक्ति

प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ ही, स्कूल-कॉलेजों की स्थापना में भूमि दान करने वाले परिवार के सदस्यों को भर्ती में वरियता देने तथा प्रत्येक विधनसभा क्षेत्र में दो-दो विद्यालयों के उच्चीकरण के प्रस्ताव विधायकों से मांग कर शीघ्र शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये।

बैठक में सचिव रविनाथ रमन, अपर सचिव एम.एम. सेमवाल, निदेशक प्राथमिक शिक्षा अजय कुमार नौडियाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल सती, अनु सचिव विकास श्रीवास्तव, अपर निदेशक पदमेन्द्र सकलानी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

कुनाल मर्डर केस का खुलासा: बहनों पर आपत्तिजनक कमेंट से आहत दोस्त ने कर दी हत्या

पथ प्रवाह, हरिद्वार

थाना कनखल क्षेत्र में बीते दिनों झाड़ियों में मिले युवक के लहलुहान शव के मामले का पुलिस ने सफल अनावरण कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के कुशल नेतृत्व में गठित टीमों ने इस ब्लाइंड मर्डर की गुथी सुलझाते हुए आरोपी दोस्त को मथुरा (उत्तर प्रदेश) से गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी प्रमोद डोबाल ने कनखल थाने में प्रेस वार्ता करते हुए ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया। बताया कि 07 फरवरी 2026 को थाना कनखल पुलिस को सूचना मिली कि श्रीयंत्र पुलिया के पास झाड़ियों में एक अज्ञात युवक का खून से सना शव पड़ा है। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू की। शिनाख्त के बाद मृतक की पहचान कुनाल पुत्र रोहिताश, निवासी रामपुर रायघाटी थाना लक्सर, हाल निवासी लाटोवाली थाना कनखल के रूप में हुई। घटनास्थल पर साक्ष्य संकलन के लिए फील्ड यूनिट को बुलाया गया। मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर थाना कनखल में मु0अ0सं0 41/26 धारा 103 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।



मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले के खुलासे के लिए पांच पुलिस टीमों का गठन किया गया। टीमों ने क्षेत्र के सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच के दौरान एक अहम सुराग हाथ लगा, जिसमें मृतक कुनाल शराब के ठेके से शराब खरीदने के बाद एक संदिग्ध स्कूटी सवार के साथ जाता हुआ दिखाई दिया।

स्कूटी सवार की पहचान, मथुरा से दबोचा

एसएसपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर स्कूटी सवार की पहचान अरविन्द उर्फ शिवम के रूप में हुई। जांच में

सामने आया कि घटना के बाद आरोपी मथुरा फरार हो गया था। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मथुरा में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पहले साथ बैठकर पी शराब, फिर विवाद में ली जान

पुलिस पूछताछ में आरोपी अरविन्द उर्फ शिवम पुत्र संदीप शर्मा निवासी पतवारी मंदिर के पीछे दुर्गा कॉलोनी थाना गोवर्धन मथुरा (उ0प्र0), हाल निवासी लाटोवाली थाना कनखल ने बताया कि वह पिछले कुछ महीनों से अपनी नानी के साथ



कनखल में रह रहा था। मृतक कुनाल उसका दोस्त था और दोनों पड़ोसी थे। 06 फरवरी की रात दोनों ने साथ बैठकर शराब पी। नशे की हालत में कुनाल ने अरविन्द की बहनों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। विवाद बढ़ने पर कुनाल ने उसे थप्पड़ भी मारे। इससे गुस्से में आकर अरविन्द ने पास में पड़े भारी पत्थर से कुनाल के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसका मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मृतक कुनाल का मोबाइल फोन बरामद किया है।

थाना कनखल पुलिस टीम:

एसएसपी देवेन्द्र सिंह रावत, व0उ0नि0 सतेन्द्र भण्डारी, अ0उ0नि0 ललित मोहन अधिकारी, अ0उ0नि0 नन्द किशोर, का0 सतेन्द्र रावत, का0 उमेद सिंह, का0 मनीष रावत, का0 विशन सिंह

सर्विलांस/सीआईयू टीम: नरेन्द्र सिंह बिष्ट (प्रभारी सीआईयू), का0 हरबीर सिंह (सीआईयू), का0 वसीम (सीआईयू), का0 नरेन्द्र कोतवाली नगर/रानीपुर टीम: उ0नि0 अंशुल अग्रवाल (को0 नगर), का0 सतीश नौटियाल (को0 नगर) का0 दीप गौड़ (रानीपुर)

5 टीमों गठित, सैकड़ों सीसीटीवी खंगाले

एसएसपी प्रमोद डोबाल ने बताया कि

एक नजर

शराब तस्कर दबोचा, कब्जे से 52 पत्ते देशी शराब बरामद



पथ प्रवाह, हरिद्वार। मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड द्वारा संचालित 'नशा मुक्त देवभूमि मिशन' को सफल बनाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद हरिद्वार के निर्देशानुसार अवैध शराब निर्माण एवं तस्करी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में भगवानपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 10.02.2026 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम खुबनपुर स्थित आम के बगीचे के पास से आरोपी सुशील पुत्र बृजपाल निवासी ग्राम सिसौना, भगवानपुर, जनपद हरिद्वार को 52 पत्ते देशी शराब (मार्का माल्टा) के साथ हिरासत में लिया विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस टीम हे0का0 खजान सिंह और कांस्टेबल संजय नेगी शामिल रहे।

पूर्व विधायक सुरेश राठौर का होटल मैनेजर नगदी और अंगूठी लेकर फरार

पथ प्रवाह, हरिद्वार। सिडकुल थाना क्षेत्र में पूर्व विधायक सुरेश राठौर के स्वामित्व वाले होटल का मैनेजर तीन लाख रुपये नकद और सोने की अंगूठी लेकर फरार हो गया। आरोप है कि जब आरोपी से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उसने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई तहरीर में सोमिल चौधरी निवासी टिहरी विस्थापित कालोनी, रानीपुर ने बताया मेरे ससुर सुरेश राठौर द्वारा अपने होटल 'रणीपुर राजवाड़ा' में एक मैनेजर नियुक्त किया गया था, जिसका नाम देवेश शर्मा है। प्रारंभ में उसने ईमानदारी से कार्य कर विश्वास जीता, जिस कारण होटल के बैंक खाते से संबंधित संपूर्ण जानकारी, चेकबुक एवं डेबिट कार्ड उसके पास उपलब्ध थे। इसके पश्चात उसने होटल के कर्मचारियों का वेतन पिछले तीन महीनों से नहीं दिया, तथा लगभग 3,00,000 (तीन लाख रुपये) नकद और एक सोने की अंगूठी लेकर बिना बताए चला गया। जानकारी के अनुसार वह पिछले तीन महीनों से हरिपुर कला, हरिद्वार क्षेत्र में रह रहा था जब हम उसके पास इस संबंध में संपर्क करने का प्रयास किया गया था उसके द्वारा गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई। सिडकुल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी नितेश शर्मा का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है, जांच के आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सघन चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध दबोचा, अवैध चाकू बरामद

पथ प्रवाह, हरिद्वार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद हरिद्वार के निर्देश पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान कोतवाली ज्वालापुर चेतक पुलिस कर्मियों द्वारा लाल पुल के पास नहर पटरी से एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध चाकू बरामद हुआ।

पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम रहीस पुत्र उमर दराज निवासी ग्राम पदार्थी, थाना पथरी, जनपद हरिद्वार बताया। आरोपी के विरुद्ध थाना ज्वालापुर में मुकदमा अपराध संख्या 109/2026 आर्मस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस टीम में



कांस्टेबल मनोज डोभाल, कांस्टेबल दिनेश कुमार शामिल रहे।

नशा तस्कर अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार

पथ प्रवाह, हरिद्वार। मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड के 'ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान' को सफल बनाने के उद्देश्य से जनपद में चलाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध अभियान के तहत भगवानपुर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है।

प्रभारी निरीक्षक भगवानपुर के नेतृत्व में थाना भगवानपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान ईदगाह कॉलोनी, भगवानपुर क्षेत्र से आरोपी जब्बर उर्फ कल्लू पुत्र जफर निवासी ईदगाह कॉलोनी शाहपुर, भगवानपुर, जनपद हरिद्वार को 4.5 ग्राम अवैध स्मैक के साथ दबोचा। आरोपी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस टीम में अ0उ0नि0 प्रदीप चौहान, कां0 दीपक ममगाई और कां0 राजेन्द्र वर्मा शामिल रहे।



नकबजनी के फरार आरोपी को चोरी के माल सहित पकड़ा

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

नकबजनी कर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले एक अभियुक्त को सिडकुल पुलिस ने चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 29 जनवरी को वादी पजानी भागवतिपन द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात चोर द्वारा ग्रापैनल्स कंपनी, सिडकुल हरिद्वार का ताला तोड़कर पीतल एवं तांबे की चोरी किए जाने के संबंध में थाना सिडकुल पर मुकदमा अपराध संख्या 36/25 अभियोग पंजीकृत किया गया।

प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक बबलू चौहान द्वारा की जा रही थी। दिनांक 10.02.2026 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मुन्ज्याल शोवा क्षेत्र से आरोपी दानिश पुत्र इरशाद, निवासी जमालपुर खुर्द, थाना कोतवाली रानीपुर,



जिला हरिद्वार को चोरी किए गए माल 04 पैकेट टर्मिनल बुश कॉपर सहित दबोचा। आरोपी के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस घटना में शामिल एक आरोपी वसीम पुत्र शराफत निवासी जमालपुर खुर्द,

थाना कोतवाली रानीपुर, जिला हरिद्वार को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस टीम में थानाध्यक्ष नितेश शर्मा, व0उ0नि0 देवेन्द्र तोमर, उ0नि0 बबलू चौहान, हे0का0 कुलदीप बगसी, का0 रोहित शामिल रहे।



कुंभ मेला-2027 की तैयारियां तेज: परामर्शदात्री समिति की बैठक में माइक्रो प्लानिंग पर मंथन

चार जनपदों में 150 वर्ग किमी क्षेत्र को मेला क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव, 32 सेक्टरों में होगा विभाजन

पथ प्रवाह, हरिद्वार

आगामी कुंभ मेला-2027 के सफल, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में मेलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में परामर्शदात्री समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें मेला व्यवस्थाओं, आधारभूत ढांचे, सुरक्षा और जन-सुविधाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों, जनप्रतिनिधियों और धार्मिक-सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से सुझाव एवं फीडबैक प्राप्त किया गया।

हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण के सभागार में आयोजित बैठक में मेलाधिकारी सोनिका ने बताया कि कुंभ मेला-2027 के लिए चार जिलों के अंतर्गत लगभग डेढ़ सौ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मेला क्षेत्र में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। इस व्यापक क्षेत्र को 32 सेक्टरों में विभाजित कर प्रत्येक सेक्टर के लिए विस्तृत माइक्रो प्लानिंग तैयार कर ली गई



है। योजना के अनुसार स्थायी एवं अस्थायी प्रकृति के सभी कार्यों को चरणबद्ध ढंग से समयसीमा के भीतर पूर्ण कराया जाएगा।

उन्होंने जानकारी दी कि प्रस्तावित मेला क्षेत्र में जनपद हरिद्वार के 23 सेक्टर, देहरादून जिले के 4 सेक्टर, टिहरी जिले के 2 सेक्टर

तथा पौड़ी गढ़वाल जिले के 3 सेक्टर शामिल किए गए हैं। प्रत्येक सेक्टर में सड़क, पेयजल, विद्युत, स्वच्छता, सुरक्षा और जन-सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है।

मेलाधिकारी ने बताया कि परामर्शदात्री

समिति से प्राप्त सुझावों को अंतिम कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाएगा, ताकि मेले का आयोजन और अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित एवं सफल बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला-2027 जैसा विशाल धार्मिक आयोजन प्रशासन और समाज के समन्वित प्रयासों से ही सफल हो सकता है।

बैठक में यह भी बताया गया कि कुंभ मेले के अंतर्गत दो स्थायी पार्किंग स्थलों के निर्माण का प्रस्ताव है। इसके साथ ही मेला क्षेत्र की आंतरिक सड़कों के सुधार, जलभराव की समस्या के समाधान तथा यातायात प्रबंधन को लेकर विशेष कार्ययोजना बनाई जा रही है। हरिद्वार नगर में सीवर लाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों को एक सप्ताह के भीतर दुरुस्त करने के निर्देश भी संबंधित विभागों को दिए गए। मेलाधिकारी ने सभी विभागों को समन्वित एवं सुनियोजित ढंग से कार्य करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती ने स्वीकृत एवं प्रस्तावित

कार्यों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया, जबकि अपर जिलाधिकारी पी.आर. चौहान ने जिला प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों की जानकारी साझा की।

बैठक में मेयर हरिद्वार किरण जैसल, मेयर ऋषिकेश शंभू पासवान, मुनि की रेती नगर पालिका अध्यक्ष नीलम बिजलवाण, भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा, श्री गंगा सभा अध्यक्ष नितिन गौतम, महामंत्री तन्मय वशिष्ठ, प्रेस क्लब अध्यक्ष धर्मेन्द्र चौधरी, युवा साधु समाज के महामंत्री रविदेव शास्त्री, धर्मशाला समिति अध्यक्ष महेश गौड़, जिला व्यापार मंडल के पदाधिकारी संजीव नैय्यर, प्रदीप कालरा, विकास तिवारी सहित विभिन्न संगठनों एवं धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सहभागिता करते हुए अपने सुझाव रखे।

इस अवसर पर एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह, एसपी (ऑफिस) जितेंद्र चौधरी, उप मेलाधिकारी आकाश जोशी, मंजीत सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

एक नजर

मैथोडिस्ट कॉलेज में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर लगायी चौपाल



पथ प्रवाह, हरिद्वार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद हरिद्वार के द्वारा महिला सुरक्षा हेतु कड़े आदेश दिए गए। जिसमें बालिकाओं व महिलाओं की सुरक्षा हेतु सार्वजनिक स्थलों एवं शैक्षणिक संस्थानों, मोहल्ला कस्बों आदि में अपराध घटित होने की संभावना के दृष्टिगत पुलिस आपके द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को पुलिस टीम ने शैक्षणिक संस्थान मैथोडिस्ट कॉलेज रुड़की में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए जागरूक करने के लिए चौपाल का आयोजन किया। इस दौरान बालिकाओं एवं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया। पुलिस टीम में पुलिस टीम उप निरीक्षक अंशु चौधरी, उप निरीक्षक चंद्रमा, महिला कांस्टेबल दीपा शर्मा, कांस्टेबल अमित रावत शामिल रहे।

जिला स्तरीय अंडर-14 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम



पथ प्रवाह, हरिद्वार। खेल निदेशालय द्वारा आयोजित जिला स्तरीय अंडर-14 आयु वर्ग (बालक एवं बालिका) की एथलेटिक्स प्रतियोगिता का बुधवार को सफल आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारम्भ जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी द्वारा हरी झण्डा दिखाकर किया गया। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि दीपक नौटियाल पार्षद नवोदय नगर ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। जिला क्रीड़ा अधिकारी शबाली गुरुंग ने बताया प्रतियोगिता में बालक वर्ग की 60 मीटर दौड़ में अंशुमन ने प्रथम, चेतन कुमार ने द्वितीय तथा सक्षम द्विवेदी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। भाला फेंक में अमन कुमार प्रथम, रवि द्वितीय और जैश पाल तृतीय रहे। लम्बी कूद में चेतन कुमार ने पहला, देव ने दूसरा तथा शिवम कश्यप ने तीसरा स्थान हासिल किया। 600 मीटर दौड़ में अंशुमन प्रथम, शिवम कश्यप द्वितीय और देव तृतीय रहे। गोला फेंक में प्रियांशु कुमार पंडित ने प्रथम, अभिषेक ने द्वितीय तथा जैश पाल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग की 60 मीटर दौड़ में रिया प्रथम, वर्णिका परमार द्वितीय एवं अंशिका तृतीय रहीं। भाला फेंक में प्रशंसा ने प्रथम, मोहिनी ने द्वितीय और वाणी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग 600 मीटर दौड़ में आरुषी सैनी प्रथम, गुनगुन द्वितीय तथा अलकिया तृतीय रहीं। गोला फेंक में प्रशंसा ने प्रथम, मोहिनी ने द्वितीय और तनिषी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। लम्बी कूद में आरुषी सैनी प्रथम, खुशी द्वितीय और गुनगुन तृतीय स्थान पर रहीं। प्रतियोगिता के सफल संचालन में निर्णायक मंडल के सदस्य अनुराग सिंह धमना, सोहनवीर सिंह, शुभम बोहरा, राजन राणा, अंकिता चौधरी एवं शिवानी नैथानी का विशेष योगदान रहा।

इस अवसर पर उपाध्यक्ष पर्वती बंधु समाज देवेन्द्र सिंह कण्डारी, महासचिव मुकेश रावत, महामंत्री युवा मोर्चा भाजपा रामनिवास, उप क्रीड़ा अधिकारी प्रदीप कुमार, सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति एवं खेल प्रेमी उपस्थित रहे।

हरिद्वार पुलिस की शराब तस्करों पर कार्रवाई

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार कोतवाली रानीपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री/तस्करी करने वालों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रानीपुर के नेतृत्व में 10 फरवरी को रात्रि में पुलिस टीम द्वारा छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस दौरान छापेमारी में पुनित पुत्र ऋषिपाल को चौहान नर्सरी के पास, चौकी गैस प्लांट क्षेत्र से हिरासत में लिया गया। मौके से आरोपी के कब्जे से 46 टेप पैक देशी शराब (माल्टा मार्का) बरामद की गई। आरोपी के विरुद्ध थाना रानीपुर पर मु0अ0सं0 48/2026 धारा



60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस टीम में कानि0 संजय रावत, का0 उदय चौहान शामिल रहे।

कुंभ मेला अधिकारी सोनिका ने कहा कि सभी कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ होंगे पूरे

पथ प्रवाह, हरिद्वार। कुंभ मेला अधिकारी सोनिका ने बुधवार को हरिद्वार प्रेस क्लब के संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने कुंभ मेले को लेकर की जा रही तैयारियों को लेकर अपनी बात मीडिया के सामने रखी। उन्होंने कहा कि सभी स्थायी प्रवृत्ति के कार्य समय से और गुणवत्ता के साथ पूरे किये जाएंगे। सभी कार्यों की गुणवत्ता की थर्ड पार्टी जांच आईआईटी रुड़की, व अन्य जांच एजेंसियां करेंगी। मीडिया से संवाद में उन्होंने कहा कि 1224 करोड़ की लागत से होने वाले कार्य समय सीमा में पूरे हो जाएंगे। प्रेस क्लब हरिद्वार के संवाद कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुंभ मेला के सभी 32 सेक्टरों को विकसित करने हेतु योजना बना ली गई है। कुंभ मेला 2027 के लिए लगभग 220 करोड़ रुपए की लागत से सीवर, सड़क, पुलों के साथ नए घाटों के निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं।

स्वीकृति मिलते ही शुरू होगा सीसीआर-2 का निर्माण

उन्होंने कहा कि बहु उद्देशीय एचएच2 को शासन से स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि रिकॉर्ड समय सभी कार्यों को पूरा करना चुनौती है लेकिन मेला अधिष्ठान में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग के खंड स्थापित होने से सभी चुनौतियों पर पार पा लिया जाएगा।

भूमि अधिग्रहण के लिए भेजी पत्रावली

हरकी पौड़ी से लगे कांगड़ा घाट विस्तार योजना पर उन्होंने कहा कि

गंगनहर में डूबा आईआईटी रुड़की का एमबीए छात्र, तलाश में जुटी पुलिस और गोताखोर टीम

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

आईआईटी रुड़की के एमबीए द्वितीय वर्ष के छात्र आशीष शुक्ला (निवासी बनारस) गंगनहर में डूबकर लापता हो गए। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भारी भीड़ एकत्र हो गई। पुलिस और जल पुलिस की टीम छात्र की तलाश में जुटी हुई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आशीष शुक्ला अपने कुछ दोस्तों के साथ गंगनहर स्थित नगर निगम पुल के पास घूमने आए थे। बताया जा

रहा है कि बातचीत के दौरान आशीष नहर के किनारे पहुंच गए। इसी दौरान अचानक उनका पैर फिसल गया और वह अनियंत्रित होकर तेज बहाव में जा गिरे। इससे पहले कि साथी छात्र कुछ समझ पाते, आशीष पानी के तेज बहाव में बहते हुए नजरो से ओझल हो गए।

घटना के बाद दोस्तों ने शोर मचाकर आसपास मौजूद लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन तेज धारा के कारण तत्काल राहत नहीं मिल सकी। सूचना मिलते ही सिविल लाइंस कोतवाली के एसएसआई मनोज गैरोला पुलिस टीम के साथ मौके पर



भूमि अधिग्रहण के लिए शासन को पत्रावली भेजी गई है। जो हमारी प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा है सभी अखाड़ों, साधु संतों से परामर्श कर व्यवस्था की जा रही है। सरकार की इच्छा और सभी 13 अखाड़ों के सानिध्य में अर्द्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भव्य दिव्य कुंभ मेला में करोड़ों श्रद्धालु के निर्विघ्न स्नान व्यवस्थाओं को मेला अधिष्ठान कृत संकल्प है।

पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर घटना की जानकारी जुटाई।

छात्र की तलाश के लिए जल पुलिस और गोताखोरों को भी बुलाया गया है। गोताखोर टीम गंगनहर में सघन सर्च ऑपरेशन चला रही है। समाचार लिखे जाने तक छात्र का कोई सुराग नहीं लग पाया था।

घटना के बाद परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि गंगनहर के किनारे सतर्कता बरतें और तेज बहाव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें।



संपादकीय

2027 चुनाव की पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री धामी के फैसले

उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव भले अभी दूर हों, लेकिन राजनीतिक सरगमियां तेज होने लगी हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हालिया निर्णयों को केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि रणनीतिक राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जा रहा है। राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में बढ़ोतरी, विभिन्न विकास योजनाओं के लिए सैकड़ों करोड़ की वित्तीय स्वीकृति, स्थानीय निकायों को संसाधन आवंटन और आधारभूत संरचना परियोजनाओं को गति-ये सभी कदम चुनावी वर्ष से पहले जनसंतोष और संगठनात्मक मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं।

सबसे पहले, राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों की पेंशन में वृद्धि का निर्णय भावनात्मक और प्रतीकात्मक दोनों स्तरों पर प्रभावी है। उत्तराखंड की राजनीति में राज्य आंदोलन की विरासत का विशेष महत्व रहा है। ऐसे में इस वर्ग को सम्मान और आर्थिक संबल देना व्यापक सामाजिक संदेश देता है कि सरकार राज्य निर्माण के मूल मूल्यों को महत्व दे रही है।

दूसरी ओर, 2397 करोड़ से अधिक की विकास स्वीकृतियां क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश के रूप में देखी जा सकती हैं। पर्वतीय जिलों में पार्किंग, सड़क, आपदा प्रबंधन और नगरीय निकायों के सशक्तीकरण जैसे निर्णय सीधे तौर पर स्थानीय समस्याओं को संबोधित करते हैं। इससे सरकार यह संकेत देती है कि वह केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं, बल्कि जमीनी विकास पर भी फोकस कर रही है।

शिक्षा, आपदा प्रबंधन, नगरीय विकास और निवेश से जुड़ी परियोजनाएं युवाओं, शहरी मतदाताओं और पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को साधने की रणनीति का हिस्सा मानी जा सकती हैं। विशेषकर आपदा मोचन निधि और मानसून में मार्गों की बहाली के लिए धनराशि अवमुक्त करना पहाड़ी राज्य की संवेदनशील जरूरतों को ध्यान में रखता है।

हालांकि, चुनावी रणनीति का असली प्रभाव क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा। यदि स्वीकृत योजनाएं समय पर पूरी नहीं होती या धरातल पर अपेक्षित परिणाम नहीं देतीं, तो विपक्ष इसे मुद्दा बना सकता है। वहीं, यदि सरकार योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर पाती है, तो 2027 में यह उसके लिए मजबूत आधार तैयार कर सकता है।

मुख्यमंत्री धामी के हालिया फैसले प्रशासनिक सक्रियता और राजनीतिक दूरदर्शिता—दोनों का मिश्रण प्रतीत होते हैं। अब देखा जाएगा कि आने वाले महीनों में विकास की रफ्तार और जनविश्वास किस दिशा में आगे बढ़ता है।

धर्म, समाज और राष्ट्र की चेतना जगाने वाले स्वामी दयानंद

योगेश कुमार गोयल

आर्य समाज के संस्थापक के रूप में वंदनीय महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के टंकारा में 12 फरवरी 1824 को हुआ था और 12 फरवरी को उनकी जयंती मनाई जाएगी। स्वामी दयानंद ऐसे देशभक्त, समाज सुधारक, मार्गदर्शक और आधुनिक भारत के महान चिंतक थे, जिन्होंने न केवल ब्रिटिश सत्ता से जमकर लोहा लिया बल्कि अपने कार्यों से समाज को नई दिशा और ऊर्जा भी प्रदान की। 1857 की क्रांति में उनका अमूल्य योगदान था। स्वामी दयानंद का बचपन बहुत अच्छा बीता लेकिन उनके जीवन में घटी एक घटना ने उन्हें इस कदर प्रभावित किया कि वे 21 वर्ष की आयु में ही अपना घर बार छोड़कर आत्मिक एवं धार्मिक सत्य की तलाश में निकल पड़े और एक सन्यासी बन गए। जीवन में ज्ञान की तलाश में वे स्वामी विरजानंद से मिले, जिन्हें अपना गुरु मानकर उन्होंने मथुरा में वैदिक तथा योग शास्त्रों के साथ ज्ञान की प्राप्ति की। 1845 से 1869 तक कुल 25 वर्षों की अपनी वैराग्य यात्रा में उन्होंने कई प्रकार के दैविक क्रियाकलापों के बीच विभिन्न प्रकार के योगों का भी गहन अभ्यास किया।

देश के स्वतंत्रता संग्राम में स्वामी दयानंद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी और 'स्वराज' का नारा उन्होंने ही दिया था, जिसे बाद में लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने अपनाया और 'स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है' का नारा दिया। वेदों का प्रचार-प्रसार करने के साथ-साथ उनकी महत्ता लोगों तक पहुंचाने तथा समझाने के लिए उन्होंने देशभर में भ्रमण किया। जीवनपर्यंत वेदों, उपनिषदों का पाठ करने वाले स्वामी जी ने पूरी दुनिया को इस ज्ञान से लाभान्वित किया। उनकी किताब 'सत्यार्थ प्रकाश' आज भी दुनियाभर में अनेक लोगों के लिए मार्गदर्शक साबित हो रही है। वेदों को सर्वोच्च मानने वाले स्वामी दयानंद ने वेदों का प्रमाण देते हुए हिन्दू समाज में फैली कुरीतियों और अंधविश्वासों का डटकर विरोध किया। जातिवाद, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी समाज में फैली

कुरीतियों को दूर करने में उनका योगदान उल्लेखनीय है, इसीलिए उन्हें 'सन्यासी योद्धा' भी कहा जाता है। दलित उद्धार तथा स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी उन्होंने कई आन्दोलन किए। हिन्दू धर्म के अलावा इस्लाम तथा ईसाई धर्म में फैली बुराईयों और अंधविश्वासों का भी उन्होंने जोरदार खंडन किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण, धार्मिक कुरीतियों की रोकथाम तथा वैश्विक एकता के प्रति समर्पित कर दिया। वे आध्यात्मिक क्रांति के संदेशवाहक थे।

स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना मुम्बई के गिरगांव में गुड़ी पड़वा के दिन 10 अप्रैल 1875 को की थी, जिसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के साथ समूचे विश्व को एक साथ जोड़ना था। आर्य समाज के द्वारा उन्होंने दस मूल्य सिद्धांतों पर चलने की सलाह दी। मूर्ति पूजा के अलावा वे जाति विवाह, महिलाओं के प्रति असमानता की भावना, मांस के सेवन, पशुओं की बलि देने, मंदिरों में चढ़ावा देने इत्यादि के सख्त खिलाफ थे और इसके लिए उन्होंने लोगों में जागरूकता पैदा करने के अथक प्रयास किए। अपने 59 वर्ष के जीवनकाल में महर्षि दयानंद ने न सिर्फ देश में व्याप्त बुराईयों के खिलाफ लोगों को जागृत किया बल्कि अपने वैदिक ज्ञान से नवीन प्रकाश को भी देशभर में फैलाया। हालांकि कई लोगों ने उनका जमकर विरोध भी किया लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती के तार्किक ज्ञान के समक्ष बड़े-बड़े विद्वानों और पंडितों को भी नतमस्तक होना पड़ा। वे अपने जीवन को पुनर्जन्म, ब्रह्मचर्य, सन्यास तथा कर्म सिद्धांत के चार स्तंभों पर खड़ा मानते थे। स्वामी दयानंद हिन्दी भाषा के प्रबल समर्थक थे और उनका मत था कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में एक ही भाषा 'हिन्दी' बोली जानी चाहिए। मानव शरीर को नश्वर बताते हुए वह कहते थे कि हमें इस शरीर के जरिये केवल एक अवसर मिला है, स्वयं को साबित करने का कि 'मनुष्यता' और 'आत्मविवेक' क्या है। वे कहा करते थे कि शक्ति किसी अलौकिकता या चमत्कारिता के प्रदर्शन के लिए नहीं होती।

माँ बाप की सेवा करना हरेक पुत्र का दायित्व है

संजय गोस्वामी

माँ बाप की सेवा करना हरेक पुत्र का दायित्व है जो आपके यश को उज्ज्वल करती है गुरु गोविंद सिंह जी के दो सबसे छोटे बेटे, साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी, जो दसवें सिख गुरु थे, उन्हें 26 दिसंबर, 1704 को सरहिंद (आज का फतेहगढ़ साहिब, पंजाब) में जबरदस्ती अपना धर्म छोड़ने से इनकार करने पर ज़िंदा दीवारों में चुनवा दिया गया और वे शहीद हो गए। वजीर खान ने धर्म परिवर्तन करने की पुरी कोशिश की प्रलोभन दिया और यहाँ तक कहा की बड़े होने पर सुन्दर सुन्दर बेगम मिलेगी लेकिन जो माता पिता का संस्कार था वो डगमगाए नहीं मरना पसंद किया और शहीद हो गया अतः आज बच्चे माता पिता को इग्नोर क्यों करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मेरी बेगम या रानी बहुत सुन्दर है वो जो कहेजी वो ठीक होगा और रात्रि में सोने का एक अलग मजा होगा सच कटु होगा लेकिन आप डाकदल में बुरी तरह से फंसे हो और दुनिया में जिम्मेदारी नाम की भी चीज होती है और पत्नी प्रेम में रखना ठीक है लेकिन माता और पिता का सहारा बनना भी जरूरी है क्योंकि जब पालन पोषण पढ़ाया लिखाया तो वो भूल क्यों जाते हो सीखो श्रवण कुमार से नहीं तो आप गकत रास्ते की ओर चल पड़े और चाह कर भी आपस में टकराव देखने को मिलता है बच्चे को अपना देखना है चाहे आपका सर जले या पेट दर्द बिमारी से परेशान हो इतना पत्नी प्रेम में ना डुबो की वृद्धा आश्रम में डाल दो इसलिए आप अपने भविष्य को देख कर ही निर्णय लो हो सकता है भगवान राम जैसा वनवास मिले लेकिन आगे का भविष्य आपको हमेशा माता पिता की दुआ देगी संस्कार अच्छा होना चाहिए सीखो श्रवण कुमार से जो दुनिया से चला तो गया लेकिन इतिहास बना दिया आप बाल बलिदान दिवस तो मानते है लेकिन सीखते क्या है गुरु गोविन्द सिंह के दो मासूम बच्चे जब अपनी कुरबानी दि होगी तो इतने छोटे से बच्चे से नहीं सीखा आप पढ़कर भी अनपढ़ से भी कहीं खराब हो

क्योंकि आपकी मानसिकता गलत तब होती है जब पत्नी प्रेम में डुबकी लगा कर आनंद से रहते हो और माता पिता को अकेले छोड़ कर पल्ला छोड़ने की कोशिश करते हो पितृभक्त पुत्र श्रवण कुमार को याद करो जिसने अपने माता पिता को टोकड़ी में लेकर तीर्थ स्थान पर ले गए और गलती से पानी लाने के चक्कर में राजा दशरथ के हाथों शिकार हो गया लेकिन माता पिता का पुत्र के प्रति प्रेम इतना था की उन्होंने राजा दशरथ को ही श्राप दे दिया और उनके पुत्र भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला और उनके वियोग में उन्होंने भी वही पीड़ा सही और स्वर्गवास हो गया इस बात को भगवान राम भी जानते होंगे लेकिन राजा सिंहासन छोड़ कर उनके वचन को निभाया राजा दशरथ उस समय यदि अपनी पत्नी कैकई के मायाजाल में ना फँसते तो शायद भगवान राम को वनवास ना मिलता और राजतिलक होता लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता ढ़ हुआ ऐ की पितृभक्त पुत्र श्रवण कुमार एक जिन्हें आज भी मातृ-पितृभक्ति के लिए जाना जाता हैं। इतिहास में मातृभक्ति और पितृभक्ति के लिए श्रवण कुमार का नाम अमर हैं। हिन्दू धर्म ग्रंथ रामायण में श्रवण कुमार का उल्लेख है। सबसे खास बात यह है कि ये वही श्रवण कुमार हैं जिनके माता-पिता के श्राप के कारण राजा पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी। श्रवण कुमार की कथा श्रवण कुमार की कथा फॉलो करें श्रवण कुमार के माता-पिता श्रवण अपने माता-पिता से अतुलनीय प्रेम करते थे। इनके माता-पिता नेत्रहीन थे इसलिए वो उनकी अत्यंत श्रद्धापूर्वक सेवा करते थे। श्रवण की मां ने उन्हें बहुत कष्ट उठाकर पाला था। श्रवण अपने माता-पिता के कामों में बहुत मदद करते थे। घर का सारा काम जैसे नदी से पानी भरकर लाना, जंगल से लकड़ियां लाना, चूल्हा जलाकर खाना बनाना आदि, श्रवण कुमार ही करते थे। माता-पिता का काम करने में वो जरा भी थकते नहीं थे बल्कि उन्हें आनंद मिलता था। माता-पिता उन्हें हमेशा आशीर्वाद देते रहते। माता-पिता की तीर्थयात्रा एक बार उनके

अंधे माता-पिता ने इच्छा जताई की उनके बेटे ने उनकी सभी इच्छाएं पूरी की है बस एक इच्छा बाकी रह गई है। उन्होंने तीर्थयात्रा करने की इच्छा जताई। श्रवण कुमार ने माता-पिता की आज्ञा मानते हुए उन्हें प्राण रहते उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दे दिया। कंधे पर कांवर लेकर और उसमें दोनों को बैठाकर वह तीर्थयात्रा करने निकल पड़े। श्रवण अपने माता-पिता को कई तीर्थ स्थानों जैसे गया, काशी, प्रयाग आदि लेकर गए और उन्हें तीर्थ के बारे में सारी बातें सुनाते रहे। ईश्वर कौन है? भगवद्गीता में किस प्रकार ईश्वर की व्याख्या की गई है? अयोध्या तीर्थ एक दिन श्रवण माता-पिता के साथ अयोध्या के समीप जंगल में पहुंचे जहा रात्रि के समय वो विश्राम कर रहे थे। उनकी माता को प्यास लगने पर वो पास ही बहती नदी से पानी लेने चले गए। श्रवण कुमार पानी लेने के लिए अपना लोटा लेकर सरयू तट पर गए। उस समय अयोध्या के राजा दशरथ थे। राजा दशरथ को शिकार खेलने का बहुत शौक था। वे रात में भी जंगल में शिकार खेलने चले जाते थे क्योंकि उन्हें शब्दभेदी बाण चलाने में महारथ हासिल थी। पावस ऋतु में सायंकाल वे धनुष-बाण लेकर सरयू के किनारे गये। उसी समय वह पर श्रवण अपने, माता - पिता के लिए जल भरने आए हुए थे। राजा दशरथ की भूल राजा रात के समय जल पीने के लिए आए किसी वन्य पशु का शिकार करना चाहते थे। अचानक पानी की कुछ आवाज सुनकर उन्हें लगा कि कोई वन्य पशु पानी पीने आया है जबकि श्रवण ने जल भरने के लिए कर्मंडल को पानी में डुबोया था। बर्तन में पानी भरने की आवाज सुनकर राजा दशरथ ने जानवर समझकर और सुनकर अचूक निशाना लगा दिया। आवाज के आधार पर उन्होंने तीर मारा जो श्रवण के सीने में जा लगा। श्रवण के मुंह से 'आह' निकल गई। राजा तीर चलाने के बाद सरयू तट पर शिकार को लेने गए तो उन्हें अपनी भूल का अहसास हुआ। उनसे अनजाने में अपराध हो गया। उन्होंने श्रवण से क्षमा मांगते हुए कहा -मुझे क्षमा करना भाई।

लोकसभा-अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास: लोकतंत्र की अग्निपरीक्षा

ललित गर्ग

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी लोकतंत्र के लिये एक चिन्ताजनक घटना है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक प्रणाली नहीं, बल्कि निरंतर संवाद, असहमति के सम्मान और संस्थागत विश्वास पर टिकी हुई एक जीवंत परंपरा है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में संसद इस लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है, जहाँ न केवल नीतियाँ बनती हैं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा बोलती है। ऐसे में जब लोकसभा अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की खबरें सामने आती हैं, तो यह घटना किसी एक व्यक्ति या दल तक सीमित न रहकर पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर देती है। विपक्षी दलों द्वारा यह आरोप लगाया जाना कि उन्हें, विशेषकर नेता प्रतिपक्ष को, सदन में बोलने का समुचित अवसर नहीं मिल रहा, और इसी आधार पर अध्यक्ष की निष्पक्षता पर सवाल उठाना, एक गहरी चिंता का विषय है। यह चिंता इसलिए भी अधिक गंभीर हो जाती है क्योंकि अध्यक्ष का पद परंपरागत रूप से सत्ता और विपक्ष के बीच संतुलन का प्रतीक माना जाता रहा है।

लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका केवल कार्यवाही संचालित करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह सदन की गरिमा, लोकतांत्रिक मर्यादा और सभी पक्षों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की संवैधानिक जिम्मेदारी भी निभाते हैं। यदि विपक्ष का एक बड़ा वर्ग यह महसूस करने लगे कि अध्यक्ष का व्यवहार पक्षपातपूर्ण है या उनकी आवाज को व्यवस्थित रूप से दबाया जा रहा है, तो यह केवल राजनीतिक असंतोष नहीं, बल्कि संस्थागत अविश्वास का संकेत होता है। 100 से अधिक सांसदों द्वारा हस्ताक्षर कर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी यह दर्शाती है कि मामला क्षणिक आक्रोश का नहीं, बल्कि लंबे समय से पनप रही असहमति और संवादहीनता का परिणाम है। लोकसभा अध्यक्ष सदन के

संरक्षक की भूमिका में होते हैं, जिनके प्रति विश्वास जरूरी होता है और उनसे भी निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है। हालांकि यह भी उतना ही सत्य है कि संख्या बल के आधार पर इस तरह का प्रस्ताव पारित होना कठिन है, लेकिन लोकतंत्र में कई बार प्रतीकात्मक कदम भी गहरे संदेश देते हैं।

विपक्षी दलों द्वारा यह स्पष्ट करना कि वे टकराव के साथ-साथ सुलह का विकल्प भी खुला रखे हुए हैं, और इसी क्रम में विभिन्न वरिष्ठ नेताओं का अध्यक्ष से मुलाकात कर संवाद का प्रयास करना, इस बात का संकेत है कि अभी भी समाधान की गुंजाइश समाप्त नहीं हुई है। यह स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर संसद जैसे सर्वोच्च मंच पर संवाद की जगह हंगामा, नारेबाजी और गतिरोध क्यों हावी होता जा रहा है। क्या यह केवल सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच अविश्वास का परिणाम है, या फिर संसदीय परंपराओं के क्षरण का संकेत? विगत वर्षों में बार-बार यह देखने को मिला है कि महत्वपूर्ण विधेयकों और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर गंभीर चर्चा के बजाय सदन की कार्यवाही बाधित होती रही है। इससे न केवल विधायी कामकाज प्रभावित होता है, बल्कि जनता के बीच यह संदेश भी जाता है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि अपने दायित्वों के प्रति गंभीर नहीं हैं।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह असहमति को स्थान देता है। विपक्ष का काम केवल विरोध करना नहीं, बल्कि सरकार को जवाबदेह ठहराना और वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना भी है। इसके लिए सदन में बोलने का अवसर, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता और आलोचना का सम्मान अनिवार्य है। यदि विपक्ष यह महसूस करता है कि उसके लिए ये रास्ते संकुचित किए जा रहे हैं, तो उसका आक्रोश सड़कों या नारेबाजी के रूप में फूट पड़ता है, जो अंततः संसद की गरिमा को ही नुकसान पहुंचाता है। दूसरी ओर, विपक्ष द्वारा बार-बार सदन की कार्यवाही बाधित करना भी उतना ही गंभीर दोष है, क्योंकि इससे शासन की प्रक्रिया ठप होती है और जनता के

मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। इस दोतरफा अविश्वास और आक्रामकता के बीच लोकतंत्र का मूल उद्देश्य कहीं खोता हुआ दिखता है।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यदि संसद बार-बार हंगामे, निलंबन और गतिरोध की खबरों में रहे, तो यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की लोकतांत्रिक छवि को प्रभावित करता है। विकास, नीति और जनकल्याण की चर्चा के स्थान पर यदि टकराव और अविश्वास केंद्र में आ जाए, तो यह भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। लोकतंत्र की मजबूती केवल मजबूत सरकार से नहीं, बल्कि मजबूत विपक्ष और निष्पक्ष संस्थानों से भी आती है। लोकसभा अध्यक्ष जैसे पद से अपेक्षा की जाती है कि वह न केवल नियमों का पालन कराए, बल्कि विश्वास का सेतु भी बने। वहीं विपक्ष से भी यह अपेक्षा है कि वह विरोध को रचनात्मक बनाए, न कि अवरोध का माध्यम।

आज आवश्यकता इस बात की है कि संसद को फिर से संवाद का मंच बनाया जाए, जहाँ तीखी असहमति भी मर्यादा में व्यक्त हो और सत्ता व विपक्ष दोनों ही लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराएँ। अविश्वास प्रस्ताव जैसे कदम यदि चेतानवी के रूप में लिए जा रहे हैं, तो उन्हें आत्ममंथन का अवसर भी बनना चाहिए। प्रश्न यह नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि यह है कि लोकतंत्र की संस्था को कैसे स्वस्थ, विश्वसनीय और प्रभावी बनाया जाए। जनता ने सांसदों को नारे लगाने या कार्यवाही बाधित करने के लिए नहीं, बल्कि देश के भविष्य पर गंभीर विमर्श के लिए चुना है। यदि संसद इस अपेक्षा पर खरी नहीं उतरती, तो लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है। यह भी तथ्य है कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में श्री ओम बिरला का संसदीय संचालन अब तक सामान्यतः अनुशासित, कार्यकुशल और नियमसम्मत माना जाता रहा है। उनके कार्यकाल में लोकसभा की कार्यवाही को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने, विधायी कार्यों को प्राथमिकता देने और विभिन्न दलों को साथ लेकर चलने का प्रयास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय, ईएसआई में 94 पद सृजित

पथ प्रवाह, देहरादून।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित की गई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेशहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट के फैसलों में ड्रा फ्री उत्तराखंड अभियान को संस्थागत मजबूती देने, वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को न्यूनतम वेतनमान प्रदान करने, कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआई) के चिकित्सा ढांचे के विस्तार, सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना की अवधि बढ़ाने, कारागार अधिनियम में संशोधन तथा बोनस संदाय संशोधन विधेयक-2020 को वापस लेने जैसे अहम विषय शामिल रहे।

एटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मिलेगा स्थायी ढांचा

ड्रा फ्री उत्तराखंड मुहिम को और प्रभावी बनाने के लिए कैबिनेट ने एटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एनटीएफ) के लिए अलग ढांचा खड़ा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्ष 2022 में गठित इस टास्क फोर्स में अब तक पुलिस बल से प्रतिनियुक्ति पर कार्रवाई लिए जाते थे।

अब राज्य मुख्यालय स्तर पर पहली बार 22 पद सृजित किए गए हैं। इनमें एक पुलिस उपाधीक्षक, दो ड्रा निरीक्षक, एक निरीक्षक, दो उपनिरीक्षक, चार मुख्य आरक्षी, आठ आरक्षी तथा दो आरक्षी चालक शामिल हैं। सरकार का मानना है कि स्थायी संरचना बनने से नशा तस्करी के विरुद्ध अभियान को और गति मिलेगी।

589 वन श्रमिकों को मिलेगा न्यूनतम 18 हजार वेतन

वन विभाग में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को



बड़ी राहत देते हुए मंत्रिमंडल ने 589 श्रमिकों को न्यूनतम 18,000 रुपये मासिक वेतन देने का निर्णय लिया है।

मंत्रिमंडलीय उप-समिति की संस्तुति के आधार पर यह फैसला लिया गया। वन विभाग एवं वन विकास निगम में कुल 893 दैनिक श्रमिक कार्यरत हैं, जिनमें से 304 को पहले से ही न्यूनतम वेतनमान का लाभ मिल रहा है। शेष 589 श्रमिक अब इस दायरे में आएंगे।

ईएसआई चिकित्सा सेवा के लिए नई नियमावली, 94 पद सृजित

राज्य मंत्रिमंडल ने 'उत्तराखण्ड कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवा नियमावली, 2026' को प्रख्यापित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत कुल 94 पद सृजित किए जाएंगे।

इनमें 76 चिकित्सा अधिकारी, 11 सहायक निदेशक, छह संयुक्त निदेशक और एक अपर निदेशक का पद शामिल है। इससे पूर्व ईएसआई के ढांचे में केवल एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) और 13 चिकित्सा अधिकारी के पद ही स्वीकृत थे। नए ढांचे से चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने की अपेक्षा है।

सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना की अवधि बढ़ी

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना की कार्यान्वयन अवधि को वित्तीय वर्ष 2025-26, अर्थात् 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना की अवधि भी एक वर्ष बढ़ाई गई है। इसी क्रम में राज्य सेक्टर की योजना को भी विस्तार दिया

गया है। भविष्य में यदि केंद्र सरकार इस योजना की अवधि आगे बढ़ाती है, तो राज्य में भी इसे स्वतः विस्तारित माना जाएगा।

कारागार अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव

मंत्रिमंडल ने उत्तराखण्ड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं (संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रारूपण को मंजूरी दी है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 'आदतन अपराधी (Habitual Offenders)' शब्द की परिभाषा राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानूनों के अनुरूप की जानी आवश्यक है। संशोधन विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में पुनः प्रस्तुत किया जाएगा।

बोनस संदाय संशोधन विधेयक-2020 वापस लेने का निर्णय

कोविड-19 महामारी के दौरान उद्योगों को राहत देने के उद्देश्य से बोनस संदाय (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020 में प्रावधान किया गया था कि आवंटनीय अधिशेष उपलब्ध होने पर ही न्यूनतम बोनस का भुगतान किया जाएगा।

हालांकि, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने इस प्रावधान पर असहमति जताई थी। वर्तमान में कोविड जैसी आपात परिस्थितियों न होने और विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त न होने के कारण इसे आगे बढ़ाया जाना संभव नहीं हो सका। इन परिस्थितियों में राज्य सरकार ने उक्त विधेयक को यथास्थिति विधानसभा से वापस लेने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं की समीक्षा

पथ प्रवाह, देहरादून।

राज्य में प्रस्तावित रेल परियोजनाओं में टनल के साथ बनने वाले एस्केप टनल को समानांतर सड़कों (पैरेलल रोड्स) के रूप में विकसित किया जा सके, इसकी व्यवस्था बनाई जाए। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना में बनी एस्केप टनल का भविष्य में किस प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता है, इसपर भी कार्य योजना तैयार जाए साथ ही कर्णप्रयाग से बागेश्वर तक रेल लाइन के विस्तार की संभावना पर भी कार्य किया जाए।

यह निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में राज्य में निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित रेल परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान दिए।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अधिकारियों को टनकपुर - बागेश्वर रेल लाइन परियोजना पर भी तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा उक्त परियोजना के अंतर्गत विभिन्न वैकल्पिक मार्गों पर भी विचार किया जाए। उन्होंने कहा परियोजना के निर्माण कार्य से अधिकांश क्षेत्र एवं जनता लाभान्वित हो सके इसके लिए अल्मोड़ा एवं सोमेश्वर क्षेत्र को भी जोड़ने की संभावनाओं पर कार्य किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा केंद्र सरकार से टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने का आग्रह किया



जाए, जिससे इसके निर्माण कार्य को गति मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित रेलवे स्टेशनों के लिए इंटीग्रेटेड प्लान बनाया जाए। जिससे इन रेलवे स्टेशनों के आसपास स्थानीय लोगों के लिए बाजार विकसित हो सके। उन्होंने कहा सभी निर्माणाधीन रेलवे स्टेशनों में स्वयं सहायता समूहों, राज्य की स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए भी विशेष व्यवस्था की जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रस्तावित रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में अभी से लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाए उन्हें होमस्टे एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जन

जागरूकता पर ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माणाधीन रेलवे स्टेशनों के आसपास स्थित विभिन्न गांव, कस्बों, धार्मिक स्थलों एवं अन्य पर्यटन स्थलों के विकास के लिए भी रोड मैप तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित रेलवे स्टेशनों के आसपास के स्थानों का समुचित पुन विकास किया जाए। ताकि रेल परियोजनाओं के निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भविष्य में बड़ी संख्या में उत्तराखंड आने वाले लोगों के आवागमन को सुविधाजनक बनाया जाए। बैठक में बताया गया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत 72.5 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है साथ ही टनल निर्माण का 95.30% कार्य



पूरा हो गया है। इस परियोजना के अंतर्गत कुछ कल 28 टनलों का निर्माण किया है जिनमें से 16 मुख्य टनल एवं 12 एस्केप टनल हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रस्तावित रेलवे स्टेशनों का निर्माण अलग-अलग थीम के आधार पर किया जा रहा है। जिसमें शिवपुरी स्टेशन को नीलकंठ महादेव, ब्यासी को महर्षि वेदव्यास, देवप्रयाग को समुद्र मंथन, जनासु को उत्तराखंड कल्चर, मलेथा को वीर माधो सिंह भंडारी, श्रीनगर को मां राज राजेश्वरी देवी, धारी देवी को मां धारी देवी, तिलनी को केदारनाथ, घोलतीर को पांच महादेव, गौचर को बाल गोविंद कृष्ण एवं कर्णप्रयाग को बद्रीनाथ मंदिर, राधा कृष्ण थीम पर आधारित निर्माण किया जा रहा है।

टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन परियोजना के बारे में बताया गया कि परियोजना के अंतर्गत रेलवे द्वारा तीन सर्वेक्षण विकल्प प्रस्तावित किए गए हैं। साथ ही अन्य वैकल्पिक मार्गों एवं अल्मोड़ा और सोमेश्वर क्षेत्र को भी इस रेल मार्ग से जोड़ने की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है।

बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव ब्रजेश कुमार संत, पंकज पांडे, मुख्य परियोजना प्रबंधक हिमांशु बडोनी, विजय, ओम प्रकाश, सुमन सिंह, कल्याण सिंह भंडारी, सनत कुमार सिंह एवं वर्चुअल माध्यम से रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 'गौदान' फिल्म का अवलोकन किया

पथ प्रवाह, देहरादून।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित सेंट्रियो मॉल, हाथीबड़कला में गाय संरक्षण पर आधारित फिल्म 'गौदान' का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने फिल्म की विषयवस्तु को भारतीय संस्कृति, ग्राम्य जीवन और गौ-संवर्धन की परंपरा से जुड़ा अत्यंत सार्थक एवं प्रेरणादायी प्रयास बताया।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गौ माता को विशेष स्थान प्राप्त है। गाय केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैविक कृषि, पोषण एवं पर्यावरण संरक्षण की आधारशिला भी है। 'गौदान' जैसी फिल्में समाज में गौ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गाय संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आधारित इस फिल्म को



राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड में टैक्स फ्री किया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस फिल्म को देख सकें और गौ संरक्षण के प्रति जागरूकता का व्यापक प्रसार हो सके। उन्होंने कहा कि यह निर्णय समाज में सकारात्मक संदेश देने वाली फिल्मों को प्रोत्साहित करने की दिशा में राज्य सरकार की

प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश में गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण, निराश्रित गोवंश के संरक्षण, पशुपालकों को प्रोत्साहन तथा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सरकार का लक्ष्य है कि गौ

आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त कर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाए। फिल्म के निर्माता विनोद कुमार चौधरी सहित पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की पावन भूमि कला, साहित्य और संस्कृति की समृद्ध धरोहर रही है। राज्य सरकार उत्तराखण्ड को फिल्म निर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रभावी फिल्म नीति लागू की गई है, जिसके अंतर्गत फिल्म निर्माताओं को आकर्षक सब्सिडी, सिंगल विंडो क्लियरेंस, शूटिंग हेतु सरल अनुमति प्रक्रिया तथा स्थानीय कलाकारों एवं तकनीशियनों को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। नई फिल्म नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और राज्य में फिल्मों का गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक वातावरण, पर्वतीय संस्कृति एवं विविध लोकेशन

फिल्मांकन के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं। सरकार का उद्देश्य है कि अधिकाधिक फिल्मों प्रदेश में शूट हों, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हों और पर्यटन को भी नई गति मिले।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा फिल्म विकास परिषद को सशक्त किया गया है तथा फिल्म स्टूडियो एवं आधारभूत संरचना के विकास की दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि 'गौदान' जैसी प्रेरक फिल्में समाज को सकारात्मक संदेश देंगी, गौ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाएंगी तथा उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, रेखा आर्य सहित अन्य जनप्रतिनिधि व बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने निर्माणाधीन गौशाला की गुणवत्ता व समयबद्धता पर दिए सख्त निर्देश

पथ प्रवाह, अल्मोड़ा

जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने पशुपालन विभाग के अधीन संचालित राजकीय चारा एवं बीज उत्पादन प्रक्षेत्र भैसवाड़ा फार्म का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी ने पूर्व दिवस भी प्रक्षेत्र का निरीक्षण किया था। बुधवार को उन्होंने पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन गौशाला के कार्यों का अवलोकन किया तथा इसके लिए चयनित स्थल का भी बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यवाही संस्था जिला पंचायत के अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप एवं तय समयसीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न करने की हिदायत भी दी।

जिलाधिकारी ने कहा कि चयनित स्थल



गौशाला निर्माण के लिए उपयुक्त है। इसके निर्माण से एक ओर जहां निराश्रित गौवंश को सुरक्षित आश्रय मिलेगा, वहीं नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रित पशुओं की समस्या के समाधान में भी मदद मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को संसाधनों का शत-प्रतिशत सदुपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए नए चयनित स्थल पर गौशाला निर्माण का

विस्तृत आगणन तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा।

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने पशुपालन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों एवं योजनाओं की भी जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि पशुपालकों को विभागीय योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण



कार्यक्रम प्रभावी ढंग से संचालित किए जाएं।

इसके उपरांत उन्होंने पशुपालन विभाग के प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण कर वहां आयोजित कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि बीते वर्ष में प्रशिक्षण केंद्र का कितना उपयोग हुआ और कितनी बार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने केंद्र की उपयोगिता का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के

निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. योगेश अग्रवाल, उपजिलाधिकारी सदर संजय कुमार, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत राजेश कुमार सहित संबंधित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

एक नजर

ऊर्जा निगम की ताबड़तोड़ छापेमारी, 66 घरों में पकड़ी बिजली चोरी



पथ प्रवाह, हरिद्वार। बिजली चोरी और बकाया बिल धारकों के खिलाफ ऊर्जा निगम ने बुधवार सुबह बड़ा अभियान चलाते हुए क्षेत्र के चार गांवों में एक साथ छापेमारी की। इस कार्रवाई में 66 घरों में अवैध रूप से बिजली का उपयोग पकड़ा गया। टीम ने मौके से चोरी में प्रयुक्त केबल जब्त कर लिए हैं और सभी आरोपियों के खिलाफ विद्युत अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कार्रवाई के बाद संबंधित गांवों में हड़कंप मच गया। अधिशासी अभियंता लक्कर देवेन्द्र कुमार के नेतृत्व में एसडीओ सचिन सचदेवा, अवर अभियंताओं और लाइनमैनों की संयुक्त टीम ने निहंदपुर सुठारी, सुल्तानपुर, टीकमपुर और जसोहरपुर गांवों में तड़के अभियान चलाया। सुबह-सुबह विभागीय टीम के पहुंचते ही बिजली चोरी करने वालों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जांच के दौरान कई घरों में मीटर से पहले केबल काटकर सीधे लाइन जोड़कर बिजली चोरी की जा रही थी। कुछ स्थानों पर ऐसे उपभोक्ता भी मिले, जिनके कनेक्शन भारी बकाया के चलते पहले ही काटे जा चुके थे और मीटर तक हटा दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दोबारा 'कटिया' डालकर अवैध रूप से बिजली आपूर्ति शुरू कर ली थी। एसडीओ सचिन सचदेवा ने बताया कि पकड़े गए 66 उपभोक्ताओं पर करीब 25 लाख रुपये का बकाया है। पूर्व में सभी के कनेक्शन विच्छेदित किए जा चुके थे, बावजूद इसके अवैध रूप से बिजली का उपयोग किया जा रहा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी के विरुद्ध विद्युत अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और नियमानुसार जुर्माना भी वसूला जाएगा। ऊर्जा निगम अधिकारियों ने दो टूक कहा कि बिजली चोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बकाया बिल जमा न करने और अवैध कनेक्शन लेने वालों के खिलाफ यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

हाथियों से डरकर बिजली के खंभे से टकराया स्कूटी सवार



पथ प्रवाह, हरिद्वार। शहर के रिहायशी इलाकों में इन दिनों जंगली हाथियों की आवाजाही से लोग डरे व सहमे हुए हैं। हरिद्वार की राजा गार्डन कॉलोनी में आए दिन जंगल से निकलकर हाथी आबादी में प्रवेश कर रहे हैं। बीते मंगलवार की रात भी ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसने स्थानीय लोगों में डर और अफरातफरी का माहौल पैदा कर दिया। यहां दो जंगली हाथी आबादी में घुस आए। अचानक हाथियों को देखकर सड़क पर मौजूद लोग घबरा गए। इसी दौरान एक स्कूटी सवार युवक हाथियों को देखकर इतना घबरा गया कि वह संतुलन खो बैठा और पास ही लगे बिजली के खंभे से जा टकराया। गनीमत रही कि युवक को गंभीर चोट नहीं आई और बड़ा हादसा टल गया। गनीमत ये भी रही कि हाथियों ने नीचे गिरे युवक पर हमला नहीं किया और कुछ देर रुकने के बाद शांतिपूर्वक आगे की ओर निकल गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि हाथियों के अचानक सामने आने से स्कूटी सवार युवक घबरा जाता है और अपना नियंत्रण खो देता है। वीडियो में कॉलोनी के भीतर हाथियों की मौजूदगी और लोगों में फैला डर भी नजर आता है। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। हरिद्वार के जगजीतपुर, राजा गार्डन और आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले लोग लगातार हाथियों की आवाजाही से भयभीत हैं।

एनएचएम के तहत केन्द्र सरकार को भेजी जायेगी एक हजार करोड़ की पीआईपी

पथ प्रवाह, देहरादून

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढीकरण एवं संवर्धन के लिये केन्द्र सरकार को वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु करीब एक हजार करोड़ की प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान (पीआईपी) भेजी जायेगी। जिसमें राज्य की वर्तमान आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये आधा दर्जन नई योजनाओं को भी शामिल किया जायेगा।

सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज अपने शासकीय आवास पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु केन्द्र सरकार को भेजी जाने वाली पीआईपी को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। जिसमें उन्होंने एनएचएम के अंतर्गत पूर्व से



संचालित कार्यक्रमों के के आलावा आशाओं का मानदेय बढ़ाये जाने, वैक्सीन स्टोरेज हेतु आवश्यक उपकरण, कोल्ड चेन उपकरण, मॉडल इम्युनाइजेशन सेंटर की स्थापना, चारधाम हेतु मोबाइल वैक्सीनेशन वैन, पर्वतीय क्षेत्रों में सेफ्टी पिट्स व वीपीडी सर्विलांस आदि को प्रमुखता से पीआईपी में शामिल करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों

को दिये। इसके अलावा उन्होंने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढीकरण के लिये राज्य के सभी सांसदगणों से भी सुझाव आमंत्रित कर पीआईपी में शामिल करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के कुछ विकासखण्डों का चयन कर मोतियाबिंद संभावित मरीजों की शतप्रतिशत जांच करने के निर्देश भी बैठक में दिये। डॉ. रावत ने प्रत्येक ब्लॉकों में चिकित्सकों के लिये आवश्यकतानुसार ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण, वृहद स्तर पर टीकाकरण अभियान का संचालन के निर्देश भी अधिकारियों को दिये।

इस अवसर पर मिशन निदेशक एनएचएम मनुज गोयल ने बताया कि राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार पीआईपी तैयार कर शीघ्र केन्द्र सरकार को भेजी दी जायेगी। जिसमें प्रदेश के सांसदगणों के सुझावों को भी शामिल किया जायेगा।

जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने बोर्ड परीक्षाओं को नकलविहीन व पारदर्शी कराने के लिए निर्देश

पथ प्रवाह, अल्मोड़ा

आगामी 21 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को सफल, पारदर्शी एवं नकलविहीन वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष होनी चाहिए और किसी भी प्रकार की अनियमितता या नकल की घटना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तत्काल तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रहे तथा प्रश्नपत्रों के सुरक्षित रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, फर्नीचर एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं समय से उपलब्ध कराई



जाएँ। जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को परीक्षा अवधि के दौरान विशेष सतर्कता बरतने तथा परीक्षा केंद्रों का रैंडम निरीक्षण और औचक चेकिंग करने के निर्देश दिए, ताकि परीक्षा प्रक्रिया की सतत निगरानी सुनिश्चित की जा सके और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।

बैठक में उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू सख्त नकल विरोधी कानून का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर भी जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने

कहा कि परीक्षार्थियों, अभिभावकों और आमजन को कानून के प्रावधानों की जानकारी दी जाए, जिससे नकल जैसी कुप्रथा पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

उन्होंने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और परीक्षा अवधि के दौरान पूरी जिम्मेदारी एवं सजगता के साथ ड्यूटी निभाने के निर्देश दिए, ताकि बोर्ड परीक्षाएं शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सकें।

जिलाधिकारी ने दिए पर्यटन संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और राजस्व वृद्धि के निर्देश

पथ प्रवाह, पौड़ी। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में जिला कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में जिला पर्यटन विकास समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान पर्यटन विभाग की परिसंपत्तियों को किराए पर दिए जाने और उनके प्रभावी संचालन पर विस्तृत चर्चा की गयी।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सतपुली स्थित एंगलर हट को शीघ्र फर्निश किया जाए और सभी विभागीय परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु आवश्यक अंशदान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि पर्यटन विभाग की परिसंपत्तियों पर



अतिक्रमण हो तो तत्काल कार्रवाई करें। खिर्सू स्थित बासा होम स्टे की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि संचालकों द्वारा किराया जमा नहीं किया जा रहा है, जिस पर

जिलाधिकारी ने सुरक्षा राशि वसूली करने तथा मरम्मत के उपरांत दोबारा टेंडर आमंत्रित करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में डांडा नागराजा स्थित रैन बसेरे के लिए ओपन टेंडर प्रक्रिया शुरू करने और श्रीनगर स्थित रैन बसेरे को बेहतर प्रबंधन हेतु नगर निगम श्रीनगर को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। जिलाधिकारी ने जिला पर्यटन विकास अधिकारी खुशाल सिंह नेगी को पौड़ी स्थित जीएमवीएन की पार्किंग का जिला विकास प्राधिकरण के साथ संयुक्त निरीक्षण कर उसे जल्द हैंडओवर करने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा।



आवास सचिव डॉ आर राजेश का औचक निरीक्षण: बायोमेट्रिक उपस्थिति की जांच

पथ प्रवाह, देहरादून

आवास विभाग, उत्तराखण्ड के सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बुधवार को बंसत विहार स्थित नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का औचक निरीक्षण कर विभागीय कार्यप्रणाली का व्यापक आकलन किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न शाखाओं में संचालित कार्यों की प्रगति, फाइलों के निस्तारण, योजनाओं के क्रियान्वयन तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। सचिव डॉ. आर. राजेश ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप गुणवत्ता और गति के साथ संपादित किए जाएं। उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करते हुए जनहित से जुड़े मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध कार्यसंस्कृति को विभागीय कार्यप्रणाली का अभिन्न हिस्सा बनाने पर विशेष बल दिया गया।

बागेश्वर एवं गरुड़ की जीआईएस आधारित महायोजना पर विस्तृत समीक्षा

निरीक्षण के उपरांत डॉ. आर. राजेश कुमार ने बागेश्वर एवं गरुड़ की जीआईएस आधारित



महायोजना (मास्टर प्लान) की समीक्षा बैठक में भाग लिया। बैठक में बागेश्वर जनपद के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों तथा जिलाधिकारी कार्यालय के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान नगरीय विस्तार, यातायात प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, जल निकासी व्यवस्था, सार्वजनिक सुविधाओं और आधारभूत संरचना विकास से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। सचिव ने निर्देशित किया कि महायोजना तैयार करते समय स्थानीय आवश्यकताओं, भौगोलिक

परिस्थितियों एवं भविष्य की जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखा जाए, ताकि क्षेत्र का योजनाबद्ध एवं सतत विकास सुनिश्चित हो सके। SASCI 2025-2026 और Deregulation 1.0 की प्रगति की समीक्षा सचिव ने SASCI 2025-2026 तथा Deregulation 1.0 के अंतर्गत संचालित कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरलीकरण एवं विनियमन शिथिलीकरण से संबंधित प्रक्रियाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए।

उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी एवं डिजिटल माध्यम से सुलभ बनाना आवश्यक है, जिससे निवेश प्रोत्साहन और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा मिल सके।

बायोमेट्रिक उपस्थिति और अनुशासन पर सख्त रुख

निरीक्षण के दौरान सचिव डॉ. आर. राजेश ने मुख्य प्रशासनिक अधिकारी से बायोमेट्रिक उपस्थिति का विवरण प्राप्त किया तथा अनुपस्थित कर्मियों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने निर्देश दिए कि बिना अनुमति अथवा अनुचित कारण के अवकाश स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बिना अनुमति अनुपस्थित कर्मियों को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि कार्यालयीन अनुशासन और समयपालन विभागीय कार्यकुशलता की आधारशिला है और इसमें किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी।

निरीक्षण के समय उपस्थित राजपत्रित अधिकारियों में बालेश्वर मुथिल (सहायक अधिकारी), संजीव कौशिक (मुख्य प्रशासनिक अधिकारी), श्रद्धा बहुगुण्डी, रूबी,

प्रीति सैनी, हिमांशु कुमार, हरीश शर्मा (सहायक नियोजकगण) तथा कु. अंजली डंगवाल (सहायक वास्तुविद् नियोजक) शामिल रहे।

निवेश और विकास को मिलेगी नई गति

डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि राज्य के संतुलित एवं सुनियोजित विकास में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने दोहराया कि सभी महायोजनाएं स्थानीय आवश्यकताओं, पर्यावरणीय संतुलन और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की जाएं।

उन्होंने कहा कि SASCI 2025-2026 एवं Deregulation 1.0 के माध्यम से प्रक्रियाओं को सरल बनाकर निवेश और विकास को गति दी जाएगी। साथ ही, कार्यालयीन अनुशासन एवं कार्यसंस्कृति को सुदृढ़ करते हुए जनता को त्वरित और प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है।

सचिव ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से टीम भावना के साथ कार्य करते हुए उत्तराखण्ड के समग्र विकास में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।

एक नजर

मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी के फुटबॉल मैचों में टीमों ने जीता खेल प्रेमियों का दिल



पथ प्रवाह, हरिद्वार। खेल महाकुंभ 2025 के अंतर्गत आयोजित राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी में फुटबॉल के अंडर-14 बालक वर्ग के मुकाबले खेले गए। जिसमें हरिद्वार ने शानदार जीत दर्ज कर सेमी फाइनल में प्रवेश किया। खेले गए मैचों में सभी टीमों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला क्रीडाधिकारी शबाली गुरुंग और नोडल मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी मुकेश कुमार भट्ट द्वारा किया गया। पहले क्वार्टर फाइनल में हरिद्वार राज्यसभा और टिहरी के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें हरिद्वार राज्यसभा ने 3-1 से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। दूसरे क्वार्टर फाइनल में चमोली और नैनीताल आमने-सामने रहे, जिसमें नैनीताल ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 6-0 से एकतरफा जीत हासिल कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में देहरादून और पौड़ी गढ़वाल के बीच मुकाबला खेला गया। इस मैच में पौड़ी गढ़वाल ने 3-1 से जीत दर्ज कर अंतिम चार में स्थान पक्का किया। चौथे क्वार्टर फाइनल में हरिद्वार लोकसभा और पिथौरागढ़ के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। निर्धारित समय तक मुकाबला बराबरी पर रहने के बाद पेनल्टी शूटआउट में हरिद्वार ने 5-4 से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

डीएम अंशुल सिंह ने पानुवानौला पार्किंग निर्माण में देरी पर जताई नाराजगी



पथ प्रवाह, अल्मोड़ा। मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत पानुवानौला में प्रस्तावित पार्किंग निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर जिलाधिकारी अंशुल सिंह की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में अब तक अपेक्षित प्रगति न होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने कहा कि वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित प्रस्ताव को पोर्टल पर अपलोड करने से पूर्व सभी आवश्यक औपचारिकताएं एवं विभागीय प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रस्ताव अपलोड करने से पहले वन विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर उसका परीक्षण अवश्य करा लिया जाए, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि या आपत्ति के कारण अनावश्यक विलंब की स्थिति उत्पन्न न हो।

उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी तालमेल के साथ निर्धारित समयसीमा में समस्त कार्यवाही पूर्ण करने तथा पार्किंग निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि पानुवानौला क्षेत्र में पार्किंग निर्माण से स्थानीय निवासियों एवं पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी, इसलिए इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी प्रदीप धौलाखंडी, कार्यदायी संस्था सीएनडीएस के अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी और एसएसपी ने मृतक पत्रकार आश्रितों को किये आर्थिक सहायता के चैक वितरित

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार गठित पत्रकार कल्याण कोष (कॉरपस फंड) से मृतक पत्रकार आश्रितों एवं गंभीर बीमारी से ग्रस्त पत्रकारों को आर्थिक सहायता का चैक जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमोद सिंह डोभाल द्वारा वितरित किए गए। इस अवसर पर पत्रकार कल्याण कोष समिति के सदस्य शशि शर्मा एवं अमित शर्मा मौजूद रहे।

इस अवसर पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा समाज के हर वर्ग का सम्मान किया जा रहा है। तथा आर्थिक रूप से कमजोर पत्रकारों को इव गंभीर बीमारी के कारण मृतक पत्रकारों के आश्रितों एवं गंभीर रूप से बीमार सक्रिय पत्रकारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है जो कि एक सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि जो पत्रकार ईमानदारी, नागरिक कर्तव्य व शासन-प्रशासन व जनता के बीच सेतु का काम करते हुए अल्पसमय में चले गए उनके आश्रित परिजनों को मुख्यमंत्री की ओर



से 5 लाख की सहायता देकर एक अभिभावक की अनुभूति कराई है। पत्रकार कल्याण कोष समिति के सदस्य शशि शर्मा व अमित शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार व सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी की सकारात्मक पहल ने पहली बार शत-प्रतिशत आवेदनों को स्वीकृत किया है। उन्होंने बताया कि 15 मृतक पत्रकारों के परिजनों व 2 गंभीर बीमारियों से ग्रस्त पत्रकारों को 5-5 लाख की आर्थिक

सहायता दी गई है। हरिद्वार जनपद से अश्विनी शर्मा पत्नी अरुण शर्मा, सरिता पत्नी अमर सिंह व चंदा देवी पत्नी नरोत्तम शर्मा तथा गंभीर बीमारी से ग्रस्त पत्रकार विवेक शर्मा को 5-5 लाख के चैक वितरित किये गए। इस दौरान एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह, प्रेस क्लब हरिद्वार अध्यक्ष धर्मेश चौधरी, जिला सूचना अधिकारी रतिलाल शाह सहित पत्रकारगण मुख्य रूप से शामिल रहे।

राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में हरिद्वार की बेटियों का परचम, मार्शल आर्ट में 7 पदक जीते

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 3 से 6 फरवरी तक आयोजित राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के अंतर्गत पेचक सिलाट (मार्शल आर्ट) प्रतियोगिता में हरिद्वार की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 पदक अपने नाम किए। प्रभारी जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी हरिद्वार मुकेश कुमार भट्ट ने बताया प्रतियोगिता में प्रदेश भर से लगभग 300-400 खिलाड़ियों (बालक एवं बालिका वर्ग) ने प्रतिभाग किया।

हरिद्वार की टीम ने अंडर-14 एवं अंडर-19 वर्ग में प्रतिभाग करते हुए उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया। पदक विजेताओं में नंदिनी (60-65 किग्रा) एवं काजल पांडेय (47-51 किग्रा) ने स्वर्ण पदक जीते। साक्षी (+65 किग्रा) ने रजत पदक हासिल किया। वहीं साक्षी (55-60 किग्रा), काजल गुप्ता (60-65 किग्रा), खुशी चौहान (51-55 किग्रा) एवं अनोखी (50-55 किग्रा) ने कांस्य पदक प्राप्त कर जनपद का नाम रोशन किया। पेचक सिलाट (मार्शल आर्ट) खेल में हरिद्वार को पहली बार इतने पदक प्राप्त हुए हैं। टीम को पिछले तीन महीनों से कोच निशा के मार्गदर्शन



में निरंतर प्रशिक्षण दिया जा रहा था। उनके समर्पण, संघर्ष और अथक परिश्रम का परिणाम है कि खिलाड़ियों ने राज्य स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में साक्षी ने रजत पदक जीतकर जनपद हरिद्वार का गौरव बढ़ाया। यह उपलब्धि पूरे परिवार और हरिद्वार के लिए गर्व का विषय है। अधिकांश खिलाड़ी मध्यमवर्गीय परिवारों से संबंध रखती हैं। सीमित संसाधनों और

अवसरों के बावजूद इन बेटियों ने अपनी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास से यह साबित कर दिया कि उचित मार्गदर्शन और निरंतर प्रयास से किसी भी स्तर पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी अब 23-24 फरवरी को दिल्ली में आयोजित 'खेलो इंडिया विमेंस लीग - नॉर्थ जोन' प्रतियोगिता में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी।



हरिद्वार-लक्सर औद्योगिक क्षेत्र को मिलेगी नई रफ्तार: त्रिवेन्द्र

पथ प्रवाह, नई दिल्ली।

हरिद्वार-लक्सर औद्योगिक क्षेत्र के सैकड़ों उद्योगों की वर्षों पुरानी मांग को बड़ी सफलता मिली है। सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा संसद में उठाए गए प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड में 'गति शक्ति मल्टी-मोडल कार्गो टर्मिनल' नीति के अंतर्गत हरिद्वार-लक्सर क्षेत्र के तीन स्थानों - पथरी, लक्सर और इकबालपुर - के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने



अपने लिखित उत्तर में यह जानकारी दी कि निजी निवेश के माध्यम से कार्गो टर्मिनलों की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु 'गति शक्ति मल्टी-मोडल कार्गो टर्मिनल' नीति लागू है। देशभर में अब तक 124 टर्मिनल (लगभग 198 मिलियन टन वार्षिक क्षमता) चालू किए जा चुके हैं तथा 280 अतिरिक्त स्थानों को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। हरिद्वार-लक्सर क्षेत्र में प्रस्तावित टर्मिनलों में पथरी - 1 फुल रिक कंटेनर साइडिंग (कंटेनर यातायात की सुविधा हेतु), लक्सर - 3 फुल रिक कंटेनर साइडिंग (कंटेनर यातायात की सुविधा हेतु) और इकबालपुर - 2 फुल रिक लाइनें (इनवर्ड

क्लंकर एवं आउटवर्ड बैगड सीमेंट की ढुलाई हेतु) उन्होंने यह भी बताया कि अंतिम स्वीकृति मिलने के पश्चात एजेंसियों को 24 माह के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा। टर्मिनलों का चयन उद्योग की मांग, संभावित कार्गो यातायात, उपलब्ध रेल अवसंरचना और क्षेत्र की समग्र लॉजिस्टिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 'प्रधानमंत्री गति शक्ति' के माध्यम से देश

में आधुनिक लॉजिस्टिक नेटवर्क का निर्माण हो रहा है, जिसका प्रत्यक्ष लाभ अब हरिद्वार-लक्सर औद्योगिक क्षेत्र को भी मिलेगा।

सांसद श्री रावत ने कहा कि इन कार्गो टर्मिनलों की स्थापना से उद्योगों को सस्ती, तेज और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन सुविधा मिलेगी, जिससे उत्पादन लागत में कमी आएगी, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। यह निर्णय उत्तराखंड को औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक हब के रूप में सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रमोद सिंह डोभाल ने किया कांवड़ पटरी मार्ग का निरीक्षण

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

शारदीय कांवड़ यात्रा को सुव्यवस्थित एवं सफलता पूर्वक संचालित करने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमोद सिंह डोभाल ने नजीबाबाद मार्ग पर चंडी चौक से थाना श्यामपुर तक अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ पटरी मार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग नजीबाबाद मार्ग पर यातायात व्यवस्था दुरुस्त रहे। उन्होंने साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश देते हुए कहा कि कांवड़ मार्ग पर विद्युत की भी समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कांवड़ मार्ग पर समुचित पेयजल व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सुविधाएं भी दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। आगामी 2027 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने एवं यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा अनुबंधित कंपनी मैसर्स पवन कुमार कंपनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को निर्देश दिए हैं कि जो भी फ्लाई ओवर एवं सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा



है उस कार्य को श्यामपुर से बहादुराबाद बाईपास तिराहे पर नीलधारा पार्किंग स्थल के लिए सर्विस लाइन मार्ग तैयार करने के निर्देश दिए, जिसके लिए उन्होंने वन विभाग, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश एवं उपजिलाधिकारी से सयुक्त निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जिसका प्रस्ताव मेलाधिकारी को प्रेषित किया जायेगा। उन्होंने कार्यवाही संस्था को निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग और

यातायात बाधित न हो, इसके लिए जो भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमोद सिंह डोभाल ने कहा कि शारदीय कांवड़ यात्रा को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए एवं आगामी कुंभ मेले को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करने के लिए यातायात व्यवस्था को ओर बेहतर करने



के लिए आज स्थलीय निरीक्षण किया गया है, जिसके लिए नीलधारा पार्किंग स्थल के लिए सर्विस लेन तैयार करने के लिए कार्यवाही संस्था को निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि यातायात प्रभावित न हो तथा यातायात सुव्यवस्थित ढंग से संचालित होता रहे। इस दौरान जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शारदीय कांवड़ यात्रा पर आए शिव भक्तों का फूल मालाओं से स्वागत

किया गया तथा अतिथि देवो भव की परंपरा से फल एवं जल पान वितरित किया गया। इस दौरान एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह, उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी आकाश जोशी, सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर हितेश कुमार, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एन के शर्मा सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

एक नजर

पंजनहेड़ी गोलीकांड के दो सप्ताह बाद भी चार आरोपी फरार

● भाजयुमो प्रदेश मंत्री के साथ एक आरोपी पर लाइसेंसी हथियार मौजूद, पीड़ितों की जान को खतरा

● मातृसदन की शिकायत पर 28 जनवरी को भूमि पैमाइश के दौरान जिप उपाध्यक्ष के भाई और रिश्तेदार पर चलाई थी गोली



पथ प्रवाह, हरिद्वार। मातृसदन की शिकायत पर एचआरडीए के आदेश पर भूमि पैमाइश के दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान के भाई और रिश्तेदार पर हुए जानलेवा हमले गोलीकांड प्रकरण के चार मुख्य आरोपियों को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जबकि दो आरोपियों के पास लाइसेंसी हथियार मौजूद है। इससे पीड़ितों के परिवार की जान को खतरा बना हुआ है। मातृसदन के ब्रह्मचारी सुधानंद की शिकायत पर एचआरडीए के आदेश पर ग्राम पंजनहेड़ी में उषा टाउनशिप में अवैध प्लॉटिंग की जांच करने के लिए जिला प्रशासन की टीम पहुंची थी। लेकिन शिकायतकर्ता के साथ पंजनहेड़ी के निवासी अतुल चौहान और उनके भतीजे भाजयुमो के प्रदेश मंत्री तरुण चौहान हथियारों से लैस होकर उषा टाउनशिप पहुंचे। वहां पर मौजूद भूमि मालिक जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान, उनके भाई सचिन चौहान, रिश्तेदार कृष्णपाल आदि मौजूद थे। बाहरी व्यक्तियों को अपनी भूमि पर आने से टोकने पर पहले से ही हथियारों से लैस होकर आए अतुल चौहान, तरुण चौहान एवं उनके साथ आए लोगों और जिप उपाध्यक्ष समेत भाईयों के बीच कहासुनी के दौरान मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान अतुल चौहान, तरुण चौहान ने अपने लाइसेंसी हथियारों से गोली चलानी शुरू कर दी। जिसमें सचिन चौहान और कृष्णपाल को गोली लग गई। जिनका एम्स ऋषिकेश में ऑपरेशन हुआ और अभी भी इलाज जारी है। इस गोलीकांड प्रकरण में अभी आरोपी भाजयुमो का प्रदेश मंत्री तरुण चौहान पुत्र दीपक, गौरव चौहान पुत्र प्रदीप कुमार, अभिषेक चौहान उर्फ सिम्मी पुत्र सतवीर, अभिषेक पुत्र त्रिलोक चंद गिरफ्तार नहीं किए जा चुके हैं। जबकि तरुण चौहान और गौरव चौहान के पास लाइसेंसी हथियार मौजूद है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान ने एसएसपी प्रमोद डोभाल से गुहार लगाई है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और इनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाएं। उन्होंने अपनी एवं परिजनों की जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। तर्क दिया है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, ऐसे में किसी पर भी हमला कर सकते हैं। पंजनहेड़ी के ग्राम प्रधान प्रदीप चौहान ने कहा है कि आरोपियों के खुलेआम घूमने से गांव में दहशत का माहौल है।

कैफे में विवाद के दौरान युवती घायल, तीन युवकों हिरासत में

पथ प्रवाह, देहरादून।

पटेलनगर क्षेत्र स्थित चंद्रबनी चौक के पास एक कैफे में दो पक्षों के बीच हुए विवाद के दौरान बीच-बचाव में लगी एक युवती घायल हो गई। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दून पुलिस ने तीन युवकों को हिरासत में लेकर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार 4 फरवरी 2026 की रात्रि को कोतवाली पटेलनगर पुलिस को सूचना मिली कि चंद्रबनी चौक स्थित 'ब्रू कैफे' में दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया है। सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा। जांच में सामने आया कि कैफे के बाहर पार्किंग क्षेत्र में हुए विवाद के दौरान माही (पुत्री हीरीश जेटली, निवासी गांधीग्राम गुरुद्वारा रोड, देहरादून) के सिर पर चोट लगी, जिसके बाद उसके साथियों द्वारा उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।

घटना के संबंध में युवती के भाई की तहरीर के आधार पर कोतवाली पटेलनगर में मु.अ.सं. 103/26, धारा 118(1) एवं 352 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस विवेचना में प्रकाश में आया कि पीड़ित युवती माही अपने दोस्तों के साथ वीकेंड पार्टी के लिए ब्रू कैफे पहुंची थी। वहीं



दूसरी ओर हिमांशु (पुत्र भंवरन सिंह, निवासी ब्रह्मपुरी निकट शिवमंदिर), पंकज रावत (पुत्र राजेंद्र सिंह, निवासी चंद्रबनी चौकला) और आयुष पवार अपने साथियों के साथ पार्टी करने आए थे। पार्टी समाप्त होने के बाद पार्किंग से वाहन निकालने के दौरान आयुष पवार और उसके साथियों की सोहेल (निवासी गांधी ग्राम) व अन्य युवकों से कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। इस दौरान पीड़िता के साथी गौतम तथा कैफे मालिक द्वारा झगड़ा शांत कराने का प्रयास किया गया। बीच-बचाव के दौरान गलती से पास खड़ी माही के सिर पर करछी लग गई,

जिससे वह घायल हो गई। युवती के घायल होने के बाद आयुष रावत और उसके कुछ साथी मौके से फरार हो गए।

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना में शामिल तीन अभियुक्तों-

पंकज रावत (18 वर्ष), निवासी चंद्रबनी चौकला, पटेलनगर

हिमांशु (19 वर्ष), निवासी ब्रह्मपुरी निकट शिवमंदिर, पटेलनगर

सूरज राणा (19 वर्ष), निवासी चंद्रबनी चौकला, पटेलनगर

को हिरासत में ले लिया है। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

हरिद्वार में परिवहन विभाग का शिकंजा, 25 चालान और 10 वाहन सीज

पथ प्रवाह, लक्सर। जनपद में सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए फेरूपुर, लक्सर और खानपुर क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार पवर्तन दल रुड़की द्वारा संचालित इस अभियान में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान 25 से

अधिक वाहनों के चालान किए गए, जबकि 10 ओवरलोड वाहनों को सीज कर संबंधित थानों में खड़ा कराया गया। कार्रवाई के दौरान सीज किए गए वाहनों में 9 डंपर शामिल हैं। इनमें से 8 डंपर खनन सामग्री (मिट्टी) का परिवहन कर रहे थे और निर्धारित सीमा से अधिक भार लेकर सड़कों पर दौड़ रहे थे। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि

ओवरलोडिंग सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है और इससे सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचता है। अभियान के दौरान परिवहन विभाग की टीम ने दो स्कूल बसों का भी चालान किया। जांच में एक बस की मैकेनिकल स्थिति अत्यंत खराब पाई गई, जिसके चलते उसकी फिटनेस सस्पेंड करने की संस्तुति की गई है।